जम्मू और कश्मीर	241
कर्नाटक	228
मध्य प्रदेश	3479
महाराष्ट्र	680
पंजाब	3236
राजस्थान	1978
उत्तर प्रदेश	8773
पश्चिम बंगाल	600
अन्य	292
समस्त भारत :	24213

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) देश में गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये 1988–89 से सात बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों यथा—बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं की एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना चलायी जा रही है । 1992–93 के दौरान, उच्च पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों सूक्ष्म पोषक तत्वों, खरपतवार नाशियों, पादक संरक्षक रसायनों, बीज उपचार रसायनों, बैल से खींचे जाने वाले अभिज्ञात उपस्करों तथा पादप संरक्षक उपस्करों के संवितरण पर प्रोत्साहन दिया गया । इसके अलावा, अपतृण नाशियों पर प्रदर्शन तथा किसानों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया । उपर्युक्त के अलावा, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र सहित सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं के मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन किया गया । इस योजना को 1993–94 के दौरान भी जारी रखे जाने की संभावना है ।

Seperate Funds for Natural Disasters

532. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any separate fund allocated by Government to meet demands caused by natural disasters expeditiously;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is any permanent agency or organisation to administer the above funds in times of need and organise relief operations in the affected areas; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVND NETAM): (a) and (b) Based on the recommendations of the IX Finance Commission, a Calamity Relief Fund (CRF) with a separate identity, has been constituted for each State with specified amount for undertaking relief opertations in the wake of natural calamities. The contribution to the Fund with an annual corpus of Rs 804.00 crores is made by the Central Government and the State Governments in the ratio of 3:1. The Central share is released in four equal quarterly instalments.

(c) and (d) A State Level Committee headed by the Chief Secretary of the respective States, is fully empowered to decide on all matters relating to the financing of relief operations in the wake of natural calamities from out of CRF including norms of assistance.

कपास का उत्पादन

533. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला भू-क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपास-उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कपास का उत्पादन करने वाले देशों में चीन, अमरीका और रुस के बाद चौथा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व में कपास-उत्पादन की दर की तुलना में भारत कपास-उत्पादन की दर लगभग आधी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1997 तक उत्पादन दर को 317 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक बढ़ाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि इस समय विश्व में यह दर 550 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर है ;

(ङ) क्या सरकार ने उत्पादकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाने का कार्य भारतीय कपास निगम को सौंपा है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा उत्पादकों को प्रति वर्ष कुल कितना बीज बेचा जाता है और उपज की प्रति हैक्टेयर दर कितनी है और वर्ष 1997 तक उत्पादकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, वर्ष 1990 में भारत कपास के उत्पादन की मात्रा में चौथा रहा। फिर भी 1991 में यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ एवं पाकिस्तान के बाद पांचवा था।

(ग) जी, हां।

(घ) लक्ष्य है कि कपास की उत्पादकता 1991–92 में 241 किलोग्राम/हैक्टेयर के स्तर से बढ़ाकर 1996–97 में 317 किलोग्राम/हैक्टेयर कर दिया जाय। विश्व में कपास की वर्तमान उत्पादकता संपूर्ण रूप से 617 किलोग्राम/हैक्टेयर है।

(ङ) एक विस्तार उपाय के रूप में, भारतीय कपास निगम से अनुरोध किया गया है कि वह लम्बे रेशे वाली दो किस्मों एवं अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन करे।

(च) निगम द्वारा कपास के बीज का उत्पादन डी सी एच–32 का 250 क्विंटल एवं एस–6 का 250 क्विंटल है। डी सी एच–32 की उपज क्षमता 20–25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जबकि एस–6 की 10–12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रत्येक उच्च उपज की किस्म के बीजों के लिए वर्ष 1997 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है (1977 एक मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि लगती है),

Drought Affected States in the Country

534. DR. SANJAYA SINH.
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of the States which are suffering from drought at present.

(b) whether it is a fact that an all Party Parliamentary Team has visited drought affected areas of the country; and

(c) if so, what remedial steps have been taken by Government to provide immediate relief to drought affected areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Government of Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Rajasthan have reported bout prevailing drought conditions in some parts of their States.

(b) Information is being collected.

(c) The concerned State Governments have initiated necessary relief operations in the affected areas which include :—

(a) Undertaking labour intensive works under Jawahar Rojgar Yojana (JRY) and Plan allocation of other concerned departments to provide employment to the affected people: